



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1144]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939

No. 1144]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/VAISAKHA 5, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

का.आ.1291(अ).—सेवाओं, प्रसुविधाओं या सहायिकियों का परिदान करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी सेवाएं सरलीकृत होती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आती है और यह फायदाग्राहियों को सीधे तौर पर सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी पात्रताओं को प्राप्त करने में समर्थ बनाता है; और आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को भी दूर करता है;

और भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मदरसों में, गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने के लिए स्कीम, एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य औपचारिक शिक्षा विषयों को शुरू करते हुए मुस्लिम छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के स्तरों को प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए मदरसों में गुणवत्तापरक सुधार लाना है और इसे राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना शिक्षक मानदेय के भुगतान के माध्यम से औपचारिक पाठ्यचर्या विषयों जैसे विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन इत्यादि के शिक्षण के लिए मदरसों की क्षमताओं को सशक्त बनाती है; और जबकि स्कीम में विज्ञान प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) भी उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम में मदरसों को औपचारिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रत्यायित केन्द्रों के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) के साथ जोड़ने का प्रावधान भी है जो ऐसे मदरसों में अध्ययन कर रहे छात्रों को कक्षा 5, 8, 10 और 12 के लिए प्रमाणन प्राप्त करने में समर्थ बनाती है; और जबकि स्कीम की मॉनीटरिंग और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य मदरसा बोर्ड को निधियां भी दी जाती हैं।

जबकि स्कीम के कार्यान्वयन हेतु छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को नियोजित किया जाता है और शिक्षकों को वेतन या मानदेय का भुगतान किया जाता है जिसमें भारत की संचित निधि से वहन किया जाने वाला आवर्ती व्यय अंतर्भूत है।

अतः अब आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक कृत्यकारियों के लिए आधार नम्बर आबंटित होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना या आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया से निकलना आवश्यक होगा।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक कृत्यकारियों, जिनके पास आधार नम्बर नहीं है या अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को 30 सितम्बर, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा जबकि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुरूप आधार नामांकन के लिए पात्र हो और ऐसे कृत्यकारी आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन करना) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित प्रभारी विभाग के लिए आवश्यक होगा कि वे कृत्यकारियों से आधार नम्बर होने का साक्ष्य प्राप्त करें। राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी अपेक्षा है कि और वे ऐसे कृत्यकारियों, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं कराया है को आधार नामांकन की सुविधा सुनिश्चित करें और यदि संबंधित ब्लॉक, तालुका या तहसील पर कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो वे वर्तमान रजिस्ट्रार के समन्वयन से सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेंगे अथवा यूआईडीएआई रजिस्ट्रार के रूप में स्वयं आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेंगे:

परन्तु जब तक संबंधित कृत्यकारियों को आधार नम्बर प्राप्त नहीं हो जाता निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्तों के अधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं कृत्यकारियों को दी जाएंगी:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन आईडी स्लिप; या

(ii) आधार नामांकन हेतु पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन की प्रति; और

(ख) (i) फोटोग्राफ सहित बैंक पासबुक; या

(ii) मतदाता पहचान पत्र; या

(iii) राशन कार्ड; या

(iv) स्थायी खाता संख्या (पीएएन) कार्ड; या

(v) पासपोर्ट; या

(vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय शीर्षपत्र में सदस्य की फोटो सहित जारी पहचान प्रमाणपत्र; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन कृत्यकारियों को सुविधाजनक तथा बाधा रहित प्रसुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक प्रबंध करेंगे, अर्थात्:-

(क) कृत्यकारियों को मीडिया तथा संबंधित विभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय, तहसील या ब्लॉक या मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूल के माध्यम से वैयक्तिक नोटिस के द्वारा वृहत प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अंतर्गत आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाया जा सके और वे यदि पहले से ही नामांकित नहीं हैं तो 30 सितम्बर, 2017 तक उनके क्षेत्रों के नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों में स्वयं को नामांकित कर सकें। स्थानीय रूप से उपलब्ध केन्द्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) उन्हें उपलब्ध करवा दी जाएगी।

(ख) यदि के अधीन कृत्यकारी उनके क्षेत्र में ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे नजदीकी स्थानों पर नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन नहीं करवा पाता है तो विभाग जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों अथवा तहसील या ब्लॉक या मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूलों आदि के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं तैयार करेगा और प्राप्तकर्ता से संबंधित स्कूल के वेबपोर्टल के माध्यम से पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट अन्य

विवरणों जैसे कि पता, मोबाईल नम्बर के साथ उनके नाम देते हुए आधार नामांकन के लिए रजिस्टर करवाने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 10-2/2017-ईई.19]

अनीता करवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education And Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2017

S.O.1291(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Human Resource Development in the Government of India is implementing the Scheme for Providing Quality Education for Madrasas (SPQEM), a Centrally Sponsored Scheme (hereinafter referred to as the scheme) which aims to bring about qualitative improvement in Madrasas to enable Muslim children to attain standards of the National Education System with introduction of formal education subjects; And whereas the scheme strengthens capacities in Madrasas for teaching of the formal curriculum subjects like Science, Mathematics, Language, Social Studies etc; And whereas the scheme also provides Science labs, Computer labs, Libraries, training of teachers and teacher learning materials; And whereas the scheme also has provision for linkage of Madrasas with National Institute for Open Schooling as accredited Centres for providing formal schooling which enable the children who are studying in such Madrasas to get certification for classes 5, 8, 10 and 12; And whereas funds are also given to the State Madarasas Boards for monitoring and popularisation of the Scheme;

And whereas, the teachers employed to impart education to children by the Madrasas for implementation of the scheme (hereinafter referred to as the functionaries), and are paid salary or honorarium (hereinafter referred to as the benefits), which involves recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Any functionary desirous of availing the benefits under the scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) A functionary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th September, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such functionaries may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department in charge of implementation of the scheme in the State Government or Union territory Administration which requires a functionary to furnish proof of possession of Aadhaar number, shall ensure Aadhaar enrolment facilities for the functionaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of the scheme in the State Government or Union territory Administration may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique identification Authority of India or by becoming Unique identification Authority of India Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar number is assigned to the functionaries, benefits under the scheme shall be given to functionaries, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) if she or he has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 ; and

- (b) (i) bank passbook with photograph; or (ii) voter identity card issued by the election commission of India; or (iii) ration card; or (iv) permanent account number (PAN) Card; or (v) passport; or (vi) driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) any other documents as specified by the State Government or Union territory Administration;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the concerned Department in the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the scheme to the functionaries, the respective Department in the State Government or Union territory Administration shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Schools. shall be given to the functionaries to make them aware of the requirement of Aadhaar number under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th September, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the functionaries under the scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the respective Department in the State Government or Union territory Administration through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Schools are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the functionaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the clause (b) to first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, to the officials of respective Department or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union territories Administrations except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 10-2/2017-EE.19]

ANITA KARWAL, Jt. Secy.